राजेश बिंदल न्यायमूर्ति के समक्ष ।

महाप्रबंधक, केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता स्टोर *याचिकाकर्ता*

बनाम

श्रम आयुक्त-सह-अपीलीय प्राधिकारी और अन्य-प्रतिवादी

2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6785

नवंबर 15, 2012

भारत का संविधान, 1950 - कला, 226 - ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 का भुगतान - अभ्यास और प्रक्रिया - पूर्व पक्षीय आदेश - को रद्द करना - याचिकाकर्ता ने पूर्व पक्षीय कार्यवाही की और कर्मचारी को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्देश जारी किया - याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील इस आधार पर खारिज कर दी गई कि याचिकाकर्ता ने अपील दायर करने से पहले ग्रेच्युटी की राशि जमा नहीं की थी - वर्तमान याचिका दायर की गई - कर्मचारी द्वारा अपने साक्ष्य बंद करने के बाद याचिकाकर्ता नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पूर्व पक्षीय कार्यवाही की गई -20 अवसरों का लाभ उठाया गया साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए याचिकाकर्ता - गैर-प्रतिनिधित्व के कारण, याचिकाकर्ता ने पूर्व पक्षीय के खिलाफ कार्यवाही की - आयोजित, साक्ष्य का नेतृत्व नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण है - हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है - सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा की गई खामियों को नियंत्रित करने की सीमा खुली नहीं हो सकती है।

वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के पास राशि जमा किए बिना या संबंधित कर्मचारी को भुगतान किए बिना अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की। अपीलीय प्राधिकारी ने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता ने कई अवसर प्रदान करने के बावजूद नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं दिया और अपील दायर करने से पहले ग्रेच्युटी की राशि जमा करने की अनिवार्य शर्त का पालन नहीं किया, इसलिए अपील खारिज कर दी।

(पैरा 5)

आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा यह दलील दी गई कि संबंधित कर्मचारी को अब प्रश्न में राशि का भुगतान कर दिया गया है, उसे अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता को नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष पूर्व पक्षीय के खिलाफ कार्यवाही की गई थी और अपील के चरण में भी सुनवाई नहीं की गई थी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि लोक प्राधिकरण द्वारा की गई चूकों को माफ करने की कुछ सीमा है। 'कई मामलों में संबंधित पक्ष के एक आदर्श पर विचार करते हुए, यह न्यायालय अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी पक्ष को ऐसा अवसर प्रदान करता है, भले ही अपील दायर करने से पहले पूर्व-जमा के प्रावधानों के अनुपालन में कुछ देरी हो, लेकिन, इस तथ्य पर

विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता एक सहकारी समिति है, कुछ मामूली खामियों के कारण इस तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

(पैरा 6)

याचिकाकर्ता के वकील *एसएस दलाल।*

ए.पी.एस. संधू प्रतिवादी नंबर 2 के लिए अधिवक्ता। (2011 के CWPNo.6910 में)

राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति

1. यह आदेश 2011 की *सीडब्ल्यूपी संख्या 6785* और *6910 वाली दो याचिकाओं का निपटारा* करेगा। तथ्यों को 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6785 से निकाला गया है।

2. याचिकाकर्ता ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (संक्षेप के लिए/अधिनियम) के तहत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 11.2.2010 (अनुलग्नक पी -3) के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, दिनांक 31-05-2010 के आदेश (संलग्नक पी-5) में दिनांक 11-2-2010 के एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन और अधिनियम के अंतर्गत उप श्रम आयुक्त-सह-अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 21-1-2011 (अनुबंध पी-7) के आदेश को खारिज करते हुए दिनांक 11-2-2010 और 31-5-2010 के आदेशों के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया गया था।

3. वर्तमान याचिका में प्रस्ताव की सूचना 16 दिसंबर को जारी की गई थी।9.2011, सेवा के बाद, प्रतिवादी नंबर 2 का प्रतिनिधित्व 28.3.2012 को किया गया था। हालांकि सुनवाई की अंतिम तारीख पर उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'आज भी इस मामले पर दो बार सुनवाई हुई। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए कोई पेश नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलें सुनी गईं।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान समय में, याचिकाकर्ता को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पूर्व पक्षीय के खिलाफ कार्यवाही की गई थी और प्रतिवादी नंबर 2-कर्मचारी को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके लिए वह हकदार नहीं था, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपील दायर करने से पहले ग्रेच्युटी की राशि जमा नहीं की थी। चूंकि याचिकाकर्ता ने अब प्रतिवादी नंबर 2 कर्मचारी को राशि का भुगतान कर दिया है, इसलिए दोनों प्राधिकरणों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को अलग रखा जाए और याचिकाकर्ता को नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष योग्यता के आधार पर अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाए।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। एक स्तरीय प्रतिवादी-कर्मचारी ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नियंत्रण प्राधिकारी

के समक्ष एक आवेदन दायर किया, याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया और उसके जवाब में जवाब दायर किया गया। प्रतिवादी-कर्मचारी के साक्ष्य के लिए आसानी को सूचीबद्ध किया गया था। जैसा कि अपील में पारित आदेश से स्पष्ट है, कर्मचारी ने 19.7.2008 को अपना साक्ष्य बंद कर दिया, इसके बाद याचिकाकर्ता के साक्ष्य के लिए मामला तय किया गया। हालांकि, 20 स्थगन का लाभ उठाने के बावजूद, कोई सबूत नहीं दिया गया था। नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता के गैर-प्रतिनिधित्व के कारण, इसे 19-1-2010 को पूर्व पक्षीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 31.5.2010 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश का अवलोकन करने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की। अधिनियम की धारा 7 (vii) के परंतुक के संदर्भ में, नियोक्ता द्वारा कोई अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है जब तक कि अपील दायर करने के समय, अपीलकर्ता या तो नियंत्रण प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि अपीलकर्ता ने उसके पास राशि जमा कर दी है या उसे अपीलीय प्राधिकारी के पास जमा कर दिया गया है। वर्तमान सरलता से, निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के पास राशि जमा किए बिना या संबंधित कर्मचारी को भुगतान किए बिना अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की। अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने कई अवसर प्रदान करने के बावजूद नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया और अपील दायर करने से पहले ग्रेच्युटी की राशि जमा करने की अनिवार्य शर्त का पालन नहीं किया, इसलिए अपील खारिज कर दी।

6. "याचिकाकर्ता द्वारा यह दलील दी जानी चाहिए कि संबंधित कर्मचारी को अब संबंधित राशि का भुगतान कर दिया गया है, उसे अपने मामले का बचाव करने का अवसर दिया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता को नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष पूर्व पक्षीय के खिलाफ कार्यवाही की गई थी और अपील के चरण में भी सुनवाई नहीं की गई थी, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा की गई चूक को माफ करने की कुछ सीमा है। हालांकि कई मामलों में संबंधित पक्ष की सदाशयता पर विचार करते हुए, यह अदालत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक पार्टी को ऐसा अवसर प्रदान करती है, भले ही अपील करने से पहले पूर्व-जमा के प्रावधानों के अनुपालन में कुछ देरी हो, लेकिन, मामला उस तरह का नहीं है जहां कुछ मामूली खामियों के कारण इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता एक सहकारी समिति है, ऐसी रियायत दी जानी है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2012 **की सिविल अपील संख्या 2474-75-चीफ** *पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और अन्य में राज्य* द्वारा अपील दायर करने में विलंब को माफ करने से इंकार करते हुए कहा है कि जब तक विलंब के लिए

स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है और सदाशयी प्रयास नहीं किया जाता है, तब तक इस सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि फाइल को कई महीनों/वर्षों तक खाते में लंबित रखा गया था प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक लाल फीताशाही की। सरकारी विभागों का विशेष दायित्व है कि वे यह दिखाएं कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर्मठता से करें।

नीचे दिए गए निर्णय चाप के प्रासंगिक पैरा:

> *12 यह विवाद में नहीं है कि संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) को इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने के माध्यम से मामले को उठाने के लिए निर्धारित अवधि सहित शामिल मुद्दों के बारे में अच्छी तरह से पता था या बातचीत हुई थी।' वे यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास सीमा की एक अलग अवधि है जब विभाग के पास अदालती कार्यवाही से परिचित सक्षम व्यक्ति थे। विश्वसनीय और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, हम एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं कि विलंब को यांत्रिक रूप से केवल इसलिए माफ क्यों किया जाए क्योंकि सरकार या सरकार का एक स्कंध हमारे समक्ष एक पक्ष है। यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विलंब के लिए क्षमा करने के मामले में जब कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या सदाशयता की कमी नहीं थी, पर्याप्त न्याय प्रदान करने के लिए एक उदार रियायत अपनाई जानी चाहिए, हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग पहले के विभिन्न निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है। अवैयक्तिक मशीनरी और कई नोट बनाने की विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण किए जा रहे दावे को आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग और उपलब्ध होने के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिसीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बांधता है।*
>
> *13. हमारे विचार में, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और उपकरणों को सूचित करने का यह सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है और सदाशयी प्रयास नहीं किए गए थे, तब तक सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रिया में काफी हद तक प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फाइल को कई महीनों/वर्षों तक लंबित रखा गया था। सरकारी विभागों का यह विशेष दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने कर्तव्यों का पालन परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ करें। देरी की माफी एक अपवाद है और इसे सरकारी विभागों के लिए प्रत्याशित लाभ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को एक ही रोशनी में आश्रय देता है और कुछ लोगों के लाभ के लिए इसे घुमाया नहीं जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न दलों का उल्लेख करने के अलावा विभाग द्वारा देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, हमारे अनुसार, विभाग इतनी बड़ी देरी को*

माफ करने के लिए पर्याप्त स्वीकार्य और ठोस कारण देने में बुरी तरह विफल रहा है। तदनुसार, विलंब के आधार पर अपीलें खारिज की जा सकती हैं।"

8. वर्तमान मामले में भी यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को नियंत्रक के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया गया था। याचिकाकर्ता को दी गई सुनवाई की 20 तारीखों पर नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य पेश नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील क्यों दायर की गई जब यह नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार राशि की पूर्व जमा की अनुपस्थिति में सुनवाई योग्य भी नहीं थी? 2007 में प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा दायर दावा याचिका में, उन्होंने 19.7.2008 को अपने साक्ष्य को समाप्त कर दिया, लेकिन ऐसे समय तक, याचिकाकर्ता को 20 स्थगन का लाभ उठाने के बावजूद 19.1.2010 को पूर्व पक्षीय के कार्यवाही की गई, और कोई सबूत नहीं दिया गया। अपने वकील की अनुपस्थिति के कारण, याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व पक्षीय कार्यवाही की गई।

9. जिस तरह से नीचे के अधिकारियों के सामने मामले को निपटाया गया था, उससे पता चलता है कि मामले की देखभाल के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था। यह मुख्य कारणों में से एक है जिसके कारण राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरणों/निकायों को न्यायालयों में छूट मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी लाखों/करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। समय आ गया है कि हर किसी को उसके काम के लिए जिम्मेदार/जवाबदेह बनाया जाए, प्राधिकरण/राज्य को अपने कर्मचारियों की लापरवाही के कारण परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आखिरकार, उन्हें काम के लिए भुगतान किया जा रहा है और वे दान के लिए काम नहीं कर रहे हैं।

10. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, मुझे रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसे खारिज कर दिया जाता है।

11. याचिकाकर्ता को उन दोषी व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करने की स्वतंत्रता होगी जो नीचे के अधिकारियों के समक्ष याचिकाकर्ता की आसानी का बचाव या मुकदमा चलाने में विफल रहे थे और उनसे नुकसान, यदि कोई हो, की राशि की वसूली कर सकते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी